BEFORE THE NATIONAL GREEN TRIBUNAL, PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI.

ORIGINAL Application No. 13/2020

IN THE MATTER OF:

Sunder Singh

.....Applicant (s)

Versus

State of Himachal Pradesh & Ors.

..... Respondent(s).

Compliance of the order passed by Hon'ble NGT on dated 21.01.2020.

MAY IT PLEASE YOUR LORDSHIP :

That the Hon'ble NGT has passed order dated 21.01.2020 in OA No. 13/2020, Sunder Singh & Anr. V/s State of HP & others as under:-

"Grievance in this application is against illegal construction on the Government forest land at Village Takoli, P.O. Panarsa, Tehsil Aut, District Mandi, Himachal Pradesh, resulting in damage to the environment. Pr.CCF (HoFF) Himachal Pradesh look into the matter and furnish a factual and action taken report within one month"

That in compliance to the order of Hon'ble NGT dated 21.01.2020 in OA. No.13/2020, Sunder Singh & Anr. V/s State of HP & ors, DFO office Mandi requested Tehsildar Aut for demarcation of disputed land bearing Khasra No 488, Muhal Kotadhar, Tehsil Aut, Distt. Mandi, HP vide letter No. T.D.R./M.C./2020- 923 dated 24.06.2020 (Copy enclosed). As per the report received from Tehsildar Aut, the status of land is **Charagah vila Drakhtan** and a case of encroachment against Sh. Bhag Chand S/o Hukame Ram on Khasra No. 488, area 00.05.00 Bigha is already under trial in the court of Tehsildar Aut under section 163 of LRA as per. (Copy enclosed).

Submitted for kind perusal, please.

5.8.2020

Deponent.

Principal Chief Conservator of Forests (HoFF)
Himachal Pradesh, Shimla-171001

BEFORE THE NATIONAL GREEN TRIBUNAL, PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI.

ORIGINAL Application No. 13/2020

IN THE MATTER OF:

Sunder Singh

.....Applicant (s)

Versus

State of Himachal Pradesh & Ors.

..... Respondent**(s).**

AFFIDAVIT

I, Ajay Kumar IFS age 60years Son of Sh. Surender Presently working as Pr. CCF (HoFF) Shimla Himachal Pradesh hereby solemnly affirm and declare on oath as under:-

That the accompanying application has been drafted at my instance and under my instructions and the contents contained therein have been read over and explained me in vernacular, which I fully understood and admitted to be correct.

I further declare on oath that the contents of this affidavit as contained above are true to the best of my knowledge; nothing relevant has been concealed therein.

Verified at Shimla on 5th August 2020

5.8.2020

Deponent

Principal Chief Conservator of Forests (HoFF)
Himachal Pradesh, Shimla-171001

क्रमांक/ 11326
वन विभाग हिमाचल प्रदेश।

दिनांक, मण्डी/ 11-3-2020

प्रेषकः— वन मण्डलाधिकारी,
मण्डी वन मण्डल, मण्डी।

प्रेषितः— तहसीलदार, औट/
तहसील सदर, जिला मण्डी हि0प्र0।

विषयः— मुहाल टकोली में खसरा नम्बर 488 की निशानदेही देने बारा।

महोदय,

उपरोक्त विषय पर वन परिक्षेत्र अधिकारी पनारसा के कार्यालय पत्र संख्या 452/पी दिनांक 03.03.2020 के कम में।

उपरोक्त संदर्भ में आपके कार्यालय को सूचित किया गया था कि माननीय एन0जी0टी0 न्यायालय के समक्ष दायर शिकायत जिसका शीर्षक सुन्दर सिंह एवं अन्य बनाम सरकार हिमाचल प्रदेश है जिसमें श्री ज्ञान चन्द पुत्र श्री भाग चन्द गांव टकोली डाकघर नगवाईं, जिला मण्डी हि0प्र0 द्वारा सरकारी वन भूमि खसरा न. 488 पर मुहाल टकोली में अवैध निर्माण करने बारे में शिकायत की गई है। अतः इस सम्बन्ध आपसे पुनः अनुरोध है कि उपरोक्त खसरा न0 की निशानदेही करने हेतू अपने अधीनस्थ कर्मचारियों को निर्देश दें कि वे जल्द से जल्द निशानदेही करें व निशानदेही के दौरान वन विभाग को भी सम्मिलित करें ताकि माननीय न्यायालय के आदेशों की अनुपालना की जा सके व वस्तुस्थिति से न्यायालय को अवगत करवाया जा सकें।

इसे अति आवश्यक समझें।

वन मण्डलाधिकारी,
मण्डी वन मण्डल, मण्डी।

Attested
Divisional Forest Officer
Mandi Forest Division

।। सुरक्षित शिक्षित मेरी लाडली, समाज को आगे ले चली।।

(7)

क्रमांकः–टी0डी0आर0 / एम0सी0 / 2020– 923

प्रेषक

तहसीलदार,
औट जिला मण्डी हि0 प्र0।

प्रेषित

वन परिक्षेत्र अधिकारी,
वन वृत पनारसा, जिला मण्डी हि0 प्र0।

दिनांकः– 24-6-2020

विषयः– **Regarding demarcation of Khasra No. 488 in Muhal Kotadhar.**

महोदय,

उपरोक्त विषय पर आपके कार्यालय पत्र संख्या 452 / पी0 दिनांक 03.03.2020 के सन्दर्भ में आपके द्वारा माननीय राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण में विचाराधीन Original Application No. 13/2020 शीर्षक Sunder Singh & ors. Vs. State of H.P. & Ors. में खसरा 488 मुहाल कोटाधार की निशानदेही चाही थी। इस सम्बन्ध में इस कार्यालय के पत्र संख्या 365 दिनांक 23.03.2020 की निरन्तरता में निवेदन किया जाता है कि दिनांक 04.05.2020 को प्रार्थियों द्वारा इस कार्यालय को अवगत करवाया गया कि इस नम्बर खसरा की निशानदेही पूर्व में दिनांक 06.03.2012 को तत्तकालीन नायब तहसीलदार औट द्वारा दी जा चुकी है। कार्यालय अभिलेख की छानवीन करने पर पाया गया कि उक्त निशानदेही के अनुसार श्री भाग चन्द पुत्र हुक्मे राम के विरूध सरकारी भूमि ख0 नं0 488 रकबा तादादी 0–5–0 बीघा भूमि पर कब्जा नाजायज की मिसल मरतब की गई है जो वर्तमान में हिमाचल प्रदेश भू–राजस्व अधिनियम की धारा 163 के अन्तर्गत इस कार्यालय में शीर्षक **सरकार बनाम भाग चन्द** विचाराधीन है।

अतः उक्त निशानदेही रिपोर्ट व मौका ततीमा की छायाप्रति आगामी कार्यावाही हेतू संलग्न प्रेषित है।

संलग्नः–उपरोक्त।

Attested
Divisional Forest Officer
Mandi Forest Division

भवदीय,

तहसीलदार,
औट जिला मण्डी हि0 प्र0।

(2)

निशानदेही रिपोर्ट
दिनांक 6.3.2012

सरकार बनाम भाग चन्द

आज दिनांक 6.3.12 को मैं अपने साथ क्षेत्रिय कानूनगो औट व पटवारी हल्का पनारसा को लेकर महाल कोटाधार में सरकारी रक्बा खसरा नम्बर 488 तादादी 4-6-12 बीघा बकिस्म चरागाह बिला दख्तान पर श्री भाग चन्द पुत्र हुक्मे राम द्वारा नाजाईज कब्जा किये गये मौका पर पंहुचा। मौका पर कासर भाग चन्द तथा वाशिन्दगान भी हाजर हुये। सबसे पहले खसरा नम्बर 480 मज़रूआ की पश्चिमी मेंड व उत्तरी मेंड के मिलान मौका को बिन्दू A मानकर पश्चिमी मेंड 31 कर्म जरीब द्वारा पैमाईश करके मौका पर निशान पत्थर रखा व इस मौका को बिन्दू B माना फिर पैमाईश को आगे बढ़ाते हुये 21 कर्म इसी मेंड को पैमाईश किया व इस मौका को बिन्दू C माना। फिर इस मौका से इसी रक्बा की दक्षिणी मेंड 20 कर्म ज़रीब चलाकर पैमाईश करके मौका पर निशान पत्थर रखा व इस मौका को बिन्दू D माना इस मौका की तसल्ली बिन्दू (मौका) B को ज़रीब से बतर डालकर की गई फासला 27 कर्म आया जो मौका व ततीमा में सही टकराव हुआ। फिर इस मौका से इसी रक्बा की पूर्वी मेंड 26 कर्म ज़रीब चलाकर पैमाईश की व आगे उत्तरी मेंड क्रमशः 7, 9, 7, 9 कर्म ज़रीब चलाकर मौका पर निशान पत्थर रखे व मौका A तक खसरा नम्बर 480 का चौमिण्डा की पैमाईश पूरी हुई। बिन्दू D पर आकर हाज़रीन को बिन्दू D,B,C त्रिकोण की तसल्ली कराई जो कासर ने सही माना। इसके बाद खसरा न0 481 की उतरी मेंड क्रमशः 17, 23 कर्म ज़रीब द्वारा पैमाईश करके मौका पर निशान पत्थर रखे व इस मौका से आगे पूर्वी मेंड 13 कर्म पैमाईश करके इस मौका को बिन्दू E माना फिर इस मौका से खसरा न0 488 में निर्मित मकान जिसे नम्बर खसरा 488/1 दर्ज किया है के पश्चिमी-दक्षिणी मिलान मौका पर ज़रीब चलाकर बतर डाला गया फासला 32 कर्म आया। फिर इसी मौका से निर्मित मकान की पश्चिमी दीवार की लम्बाई 12 कर्म पैमाईश की गई इस मौका की तसल्ली खसरा नम्बर 485 की पूर्वी-दक्षिणी मेंड के मिलान मौका से बतर डालकर की गई फासला 20 कर्म आया जो ततीमा व मौका पर सही टकराव हुआ। फिर इस मौका से मकान की उतरी मेंड दीवार 5 कर्म पूर्वी दीवार 7 कर्म फिर उतरी मेंड 8 कर्म व फिर पूर्वी दीवार 5 कर्म तथा दक्षिणी मेंड 13 कर्म की पैमाईश करके मौका पर निशान पत्थर रखे। इस मौका की तसल्ली खसरा नम्बर 504/1 की उतरी व पश्चिमी मेंड के मिलान पर बतर डालकर की गई फासला 8 कर्म आया जो सही टकराव हुआ। इस पैमाईश को कासर व वाशिन्दगान ने सही माना। इस प्रकार कासर द्वारा खसरा नम्बर 488/1 तादादी 0-4-5 बीघा में मकान का और निर्माण करना पाया गया तथा मकान का रक्बा 0-5-0 बीघा कब्जा में पाया गया। ब्यानात कासर व अन्य वाशिन्दगान के कलमबन्द किये गये तथा अन्य राजस्व दस्तावेज के साथ शामिल मिसल है।

नायब तहसीलदार,
उप तहसील औट।

Attested
Divisional Forest Officer
Mandi Forest Division

06-07 मौजा [illegible] परगना [illegible] तहसील [illegible] जिला [illegible]

D.L. R. Form No. 5

(सावन्दी)	नम्बर खतौनी	नाम पति या तरफ मय नाम नम्बरदार व तादाद मुआनला	नाम मालिक व ऐहवाल	नाम काश्तकार व ऐहवाल	नाम चाह व दीगर बसायल आबपाशी	नम्बर हाय खसरा	रकबा हर खेत व मिजान खाता मय किस्म अराजी		[illegible]	हिस्सा या पैमाना हकीयत व तरीका बाछ	मुताल्लक [illegible] मुआनला व [illegible]	कैफियत
							बीघों में	मीट्रिक इकाईयों में				
1	2	3	4	5	6	7	8		9	10	11	12
[illegible]	576/[illegible]		सरकार हिमाचल प्रदेश	[illegible] मालिक [illegible]		488	4-6-12 [illegible]				X	

[illegible]

Attested
Divisional Forest Officer
Mandi Forest Division

136

NO.FFE-B-F (9)-2/2009-L
Government of Himachal Pradesh
Department of Forests

From

The Principal Secretary (Forests) to the
Government of Himachal Pradesh.

To

The Pr. Chief Conservator of Forests,
Himachal Pradesh, Shimla-01

Dated: Shimla-2, 4-10-2013

Subject:- Regarding encroachment on Govt. Forest Land.

Sir,

P-205

I am directed to refer to your letter No. Ft.67-35/84(M) Mandi-Vol-IV dated 21-08-2013 on the subject cited above and to say that the matter has been examined and has been decided that the eviction proceedings against the encroacher shall continue to initiate by the Revenue Department under section 6 of Himachal Pradesh Land Revenue Act. 1954. You are, therefore, requested to transfer such cases to Revenue Department. The Divisional Forest Officer's would exercise the Juridiction only over such Land as has been specifically classified as Forest or recorded in the possession of the Forest Department.

Yours faithfully,

(Parkasha Nand)
Under Secretary (Forests) to the
Government of Himachal Pradesh.
(Office) Ph.No.-0177-2880818.MoNo.9419455573
(Email.usforest.hp@gmail.com)

Conservator of Forests (H.P.)

Endst.No. As above Dated: Shimla-171002 the 2013.

Copy forwarded to Deputy Secretary (Revenue) to the Government of Himachal Pradesh. He is requested to issue instructions to the Revenue Officers to initiate proceedings under the Land Revenue Act.

(Parkasha Nand)
Under Secretary (Forests) to the
Government of Himachal Pradesh.
(Office) Ph.No.-0177-2880818.MoNo.9419455573
(Email.usforest.hp@gmail.com)

Attested
Divisional Forest Officer
Mandi Forest Division

Ft. 67-35/84 I.IV.
H.P. Forest

From:

Principal Chief Conservator of Forests(HoFF)
Himachal Pradesh, Shimla

To:

The Additional Chief Secretary (Forests)
to the Govt. of Himachal Pradesh,
Shimla

Dated Shimla-1, the

Subject: Regarding encroachment on Govt. Forest land.

Sir,

Conservator of Forests, Mandi has reported that some cases/missals of encroachment on Govt. land pertaining to Gairmumkin, Charagah Drakhtan, Charagahbilla Drakhtan etc. categories of Govt. lands have been received from Assistant Collector,(Ist Grade) Sundernagar, Tehsildar Sundernagar, Sarkaghat, Sadar & Naib Tehsildar Baldwara, Nihri with their remarks that all the Govt. land is forest land, therefore, the encroachment cases pertaining to forest land classified as Gairmumkin, Charagah Drakhtan, Charagah Billa Drakhtan etc. are essentially required to be tried by Divisional Forest Officer concerned.

2. In this regard, it is, also submitted that as per Govt. Notification No. 1-21/71-LSG dated 08.06.1994 (photocopy enclosed annexure-I) the cases were returned to the concerned revenue authorities with the remarks that such land was not in our possession physically or on record, hence these cases cannot be tried under H.P. Public Premises Land (Eviction & Rent Recovery) Act.

3. It is further submitted that the issue with regard to challanning these cases have been discussed by senior Forest Officers at many fora with the legal expert including Secretary Law specially during the trainings on legal issues when it was concluded that for the DFOs it would be legally appropriate, if case pertaining to the forest land, which are in our possession and recorded as "Kabza Van Vibhag" in the revenue records are tried as per the HP Government notification dated 8.6.94 empowering DFOs for the eviction proceedings. For all other categories Gairmumkin, Charagah Drakhtan, Charagah Billa Drakhtan etc., the cases be challaned in the revenue courts as the issues of eviction, adverse possession etc. can be better redressed in land Revenue Act.

Attested
Divisional Forest Officer
Mandi Forest Division

(126)

4. The stand taken by the revenue officers that all waste land cases should be tried only by the Collector-cum-DFOs as all the waste land attract Forest Conservation Act, 1980, does not hold good as the FCA, 1980 is applicable even in private forest land and Government forest land in possession with other departments. The mandate of FCA, 1980 should not be seen as a reason to entrust all such cases to the Forest Department.

5. It is also worthwhile to mention that most of such cases now being tossed back to the forest department pertain to the revenue misals, 2002-2003. At no stage at that time forest officials were involved in making these misals and the forest officials do not have any knowledge regarding the nature and location of these cases.

6. In the similar cases in the past in the court of Ld. Divisional Commissioner, Mandi, it has been ordered that DFO-cum-Collector do not have any jurisdiction over such category of land (copy of case Braham Dass Vs State of H.P. is attached annexure-II).

7. In view of above, it is requested that matter may kindly be examined at Govt. level and necessary guidance whether cases in which land in question is either Gairmumkin, Charagah Dra ntan, or Charagah Billa Drakhtar but is neither in the physical possession nor on record of Forest Deptt. are required to be challaned under H.P. Public Premises Land (Eviction & Rent Recovery) Act, 1971 by DFOs-cum-Collector (Forests) as per Govt. Notification No. 1-21/71-LSG dated 8.6.94 or not.

An early clarification is solicited please.

Yours faithfully,

Principal Chief Conservator of Forests (HoFF)
Himachal Pradesh.

30/8/13

Encl: As above

Endst. No. Ft. 67-35/84(M)Mandi-Vol.IV. Dated Shimla-1, the 21 AUG 20

Copy to CF Mandi w.r.t his Memo.No D.VIII-6(M)/2238 dated 12.06.2013 for information. He is requested to pursue the matter at Govt. level by deputing an officer well conversant with the facts of the case.

Attested
Divisional Forest Officer
Mandi Forest Division

Principal Chief Conservator of Forests (HoFF)
Himachal Pradesh.

Endst No. D-VIII-6(M)/4883-87 dated 28 AUG 201

Copy is forwarded to DFO SUKET w.r.to this office endst No 2239 dated 12-6-2013 for information taking fur action he's request to pursue the matter at his own level. All DFO's (except SUKET) for information and similar action.